

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 12 दिसम्बर 2024 गुरुवार

सम्पादकीय

बदलते जीवन शैली का संकेत

यह मौजूदा वक्त की विडंबना है कि आय बढ़ने के साथ लोगों ने घर में बने खाने की बजाय डिब्बाबंद प्रसंस्कृत खाने को तरजीह देना शुरू कर दिया है। सूचना माध्यमों के जरिये तुरत-फुरत के खाने के विज्ञापनों का इतने आक्रामक ढंग से प्रचार किया जाता है कि बच्चे क्या, बड़े भी डिब्बाबंद खाने के मुरीद होने लगते हैं। यह जानते हुए कि यह उनकी सेहत पर भारी है। जब घर के बड़े-बुजुर्ग इससे बचाव की सलाह देते हैं तो वे इसे पुरातनपंथी सोच करार दे देते हैं। लेकिन डिब्बाबंद खाने की मुहिम चलाने वाले पश्चिमी देशों को भी अब अहसास हो चला है कि डिब्बाबंद खाने से समय से पहले बुढ़ापा दस्तक देने लगता है। खानपान की पश्चिमी संस्कृति के वाहक इटली में हुए एक शोध ने विकसित देशों को भी नींद से जगाया है। दरअसल, इटली के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी के एक हालिया शोध ने फ्रिज बढ़ाने वाला निष्कर्ष दिया है कि डिब्बाबंद भोजन के जरूरत से ज्यादा सेवन से व्यक्ति का शरीर समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इसके सेवन से हमारे शरीर की कोशिकाएं और उतक समय से पहले वृद्ध होने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करता है तो बुढ़ापा जल्दी आएगा। इस शोध में करीब साढ़े बाइस हजार लोगों को शामिल किया गया। निष्कर्ष में पाया गया कि अधिक मात्रा में जंक फूड व प्रसंस्कृत भोजन का उपभोग करने वाले लोगों की जैविक उम्र अधिक दर्ज की गई। वैज्ञानिकों का दावा है कि हमारे खाने में शामिल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के मुक्त कण अन्य स्क्वन्थ अणुओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया देते हैं। चिंता की बात यह है कि ये न केवल डीएनए व आरएनए बल्कि प्रोटीन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जिससे समय से पहले ही शरीर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। अंततः शरीर समय से पहले बूढ़ा होने लगता है।

वहीं आशंका जतायी जा रही है कि रासायनिक पदार्थों द्वारा संरक्षित डिब्बाबंद खाना हमारे शरीर में सूजन भी पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं कालांतर व्यक्ति मोटापा, हृदय रोग, दूसरी श्रेणी के मधुमेह व गठिया जैसे रोगों का भी शिकार हो सकता है। दरअसल, खाद्य पदार्थों का बाजार चलाने वाली कंपनियों की कोशिश होती है कि खाने को देर तक संरक्षित किया जाए। खाद्यान को प्रसंस्कृत करने के लिये सुरक्षित रखने वाले रासायनिक पदार्थों से सोडियम का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अधिक मात्रा में चीनी तथा शरीर के लिये नुकसानदायक रसायन, वसा व कार्बोहाइड्रेट भी खाने को देर तक चराने लायक बनाने के लिये इस्तेमाल किए जाते हैं। जो आखिरकार हमारी सेहत से खिलवाड़ ही करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ कंपनियां अधिक मात्रा में स्टाच का भी प्रयोग करती हैं। ये कालांतर शरीर में शर्कर बढ़ने से मधुमेह का खतरा पैदा कर सकती हैं। अधिक तेल भी सेहत के लिये घातक होता है। सेहत वैज्ञानिक लंबे अरसे से कहते रहे हैं कि डिब्बाबंद खाने व जंकफूड शरीर में मोटापा बढ़ाता है। दरअसल, इसमें लिपिडान ट्रांस फैट कालांतर शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इससे बाद में कई तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। विशेषकर दिल के रोगों के लिये यह घातक साबित हो सकता है। एक अछे ययन बताया है कि हाल के वर्षों में भारतीयों के खाने में डिब्बाबंद भोजन का हिस्सा बढ़ा है। एक भारतीय रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि नई पीढ़ी घरों में खाना बनाने के बजाय डिब्बाबंद खाने को तरजीह दे रही है। जो कालांतर गैर संक्रामक रोगों को ही बढ़ावा देता है। विडंबना यह कि शोध व बच्चे डिब्बाबंद खाने और कार्ट फूड को अपना मुख्य भोजन बना रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी उम्र में होने वाले लाइफस्टाइल के रोग अब बच्चों व किशोरों में भी होने लगे हैं। निश्चित ही इटली में हुआ शोध हमारी आंख खोलने वाला होना चाहिए। लोगों को डिब्बाबंद भोजन से परहेज करने के लिये जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।

यूपी में बदलते सियासी समीकरण



—अजय कुमार—

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से सियासी समीकरण काफ़ी तेजी के साथ बदल रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार की विरोध की हाजी नहीं पक पाने के कारण प्रदेश में एक बार फिर से नए सियासी समीकरण उभरते नजर आ रहे हैं। इस नये समीकरण में तुलनात्मक कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के अहम रोल हो सकता है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को दिये जाने की मांग का भी सम्भल कर रहे हैं। यह संकेत के अंदर भी सभा-कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर मजबूती से एक साथ नहीं दिख रहे हैं। संपा नेताओं का कहना है कि संभल मामले में उसके सांसद पर मुकदमे दर्ज किए जाने का कांग्रेस ने उस तरह विरोध नहीं किया जैसी उससे अपेक्षा थी। बताते हैं कि लोकसभा में फंजावट (अयोध्या) की सीट सांसद अवधेश प्रसाद की सीट पीछे होने पर भी दोनों दलों के रिश्तों में दरार आई है। सभा का मानना है कि



बैक में सेमरारी की कोशिश कर रही है। सभा-कांग्रेस के बीच दूरियां लगातार बढ़ने के साथ एक-दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से बयानबाजी भी हो रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की नाकामी भी इसमें एक अहम कड़ी समझा जा रहा है। यही दूरियां हो गई हैं कि संसद के अंदर भी सभा-कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर मजबूती से एक साथ नहीं दिख रहे हैं। संपा नेताओं का कहना है कि संभल मामले में उसके सांसद पर मुकदमे दर्ज किए जाने का कांग्रेस ने उस तरह विरोध नहीं किया जैसी उससे अपेक्षा थी। बताते हैं कि लोकसभा में फंजावट (अयोध्या) की सीट सांसद अवधेश प्रसाद की सीट पीछे होने पर भी दोनों दलों के रिश्तों में दरार आई है। सभा का मानना है कि

सीटिंग प्लान पर बात के समय कांग्रेस ने उसे मरोसे में नहीं लिया। वहीं, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि संसद में अदाणी मामले में उसे सभा का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। हाल यह है कि जेल में बंद सभा के कड़ावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने भी इंडिया ब्लॉक को जेल से एक संदेश भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक को मुसलमानों पर हो रहे हमलों पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी लिखा कि संभल की घटना के जेसे ही कांग्रेस में हुए अत्याचार का मुद्दा भी संसद में उतनी ही मजबूती से उठाना चाहिए। कांग्रेस और सभा के बीच दूरियां तब और बढ़ गईं जब सभा कि तरफ से कहा जाने लगा कि

इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस की जगह तुलनात्मक कांग्रेस की सुयोग्य ममता बनर्जी को दिए जाने पर सभा को एतराज नहीं है। बता दें लोकसभा चुनाव के बाद कई चुनावों में कांग्रेस की लगातार हार के बाद इंडिया गठबंधन में अंतर्विरोध बढ़ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि यूपी की राजनीति एक बार फिर पुनर्रचना की जा सकती है। सभा और कांग्रेस के बीच कई दूरियों का सियासी लाभ सभा को मिलने की उम्मीद है। पार्टी जैसी से बदलते राजनीतिक घटना पर नजर बनाए हुए है। यदि कांग्रेस और सभा के बीच बात नही तो इसकी वजह से बने नये तारे सभा को बाधना आम बन सकती है। जाणकारों की मानें तो वर्तमान में पार्टी को अपना

पर भी दोनों दलों के रिश्तों में अपनहजता पैदा हुई है। सभा का मानना है कि सीटिंग प्लान पर बात के समय कांग्रेस ने उसे मरोसे में नहीं लिया। वहीं, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि संसद में अदाणी मामले में उसे सभा का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। हालांकि इसका लाभ उसे लोकसभा चुनावों में भी मिलाता गया। वर्ष 2012 में बसपा ने फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जो तब साबित हुआ। यही हाल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ। 2019 में बसपा ने सभा के साथ गजोजंड कर लोकसभा चुनाव लड़ा और 10 सांसदों वाली पार्टी बन गई। हालांकि इसके बाद वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने से उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ गया। अब पार्टी की उम्मीद तीसरा मोर्चा बन पर टिकी है। ऐसे में बेहतर होगा कि गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी करें। भाजपा को मानें दने के लिए रणनीति के साथ जनता के बीच लगातार जुट रहने की जरूरत है।

बात बीएसपी की भी जाए तो हरियाणा व महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस व सभा के बीच बढ़ती दूरियों का सियासी लाभ सभा को मिलने की उम्मीद है। पार्टी जैसी से बदलते राजनीतिक घटना पर नजर बनाए हुए है। यदि कांग्रेस और सभा के बीच बात नही तो इसकी वजह से बने नये तारे सभा को बाधना आम बन सकती है। जाणकारों की मानें तो वर्तमान में पार्टी को अपना

राजनीति की नयी डगर पर प्रियंका गांधी



—निर्मल रानी—

देश में पिछले दिनों जहाँ महाराष्ट्र व झारखण्ड में विधानसभा चुनाव संपन्न हुये वहीं विभिन्न राज्यों की कई सीटों पर विधानसभा व लोकसभा उपचुनाव भी करायें गये। इन्हीं में एक केरल की वायनाड संसदीय सीट भी थी जिस पर 2024 के आम चुनावों में राहुल गांधी भावबल्लेरी के साथ साथ वायनाड में भी विजयी हुये थे। बाद में राहुल को वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली की सीट अपने पास रखनी पड़ी। राहुल ने यहाँ 6,47,445 वोट प्राप्त करके 3,64,422 के अंतर से भारी जीत हासिल की थी। इसी सीट पर हुये उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पहली बार लोकसभा चुनाव में उतारा। प्रियंका को यहाँ राहुल गांधी से भी अधिक मत हासिल हुये और उन्होंने 4 लाख से अधिक वोटों के अंतर से प्रत्यक्ष सीट जीत हासिल की। जिस समय प्रियंका की शादीवार व संसदीय राजनीति में उनके सक्रिय व अधिकृत प्रवेश की पुष्टिका वायनाड की जनता लिख रही थी उस समय देश का राष्ट्रीय मीडिया व केरल महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों को महिमागीत कर रहे में लगा था।

गौर तलब है कि अपने व्यक्तिगत में अपनी दादी इंदिरा गांधी की दर्शन का एहसास कराने वाली प्रियंका गांधी को पहली बार इतने भारी मती से उस केरल राज्य के लोगों ने चुना है जोकि देश के सबसे शिक्षित राज्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयासों के बावजूद यहाँ अपनी दाल नया नहीं डाल पाई। केरल के लोग भाजपा को वोट क्यों नहीं देते इसपर कांग्रेस या विश्व क्या कहता है उससे ज्यादा अभिमान यह बात की है कि स्वयं भाजपा इस बारे में क्या सोचती है। इस विषय पर जब मार्च 2021 में केरल भाजपा के राष्ट्रीय उपध्यक्ष व केरल भाजपा के अध्यक्ष रहे वरिष्ठ नेता राजगोपाल से पूछा गया कि बीजेपी केरल में अपनी राजनीतिक नीतियां क्यों नहीं तैयार कर पाती। इस प्रश्न के उत्तर में राजगोपाल ने कहा, शकलेंक अवसर तक का प्रवेश है। जो-तन प्रमुख कारण है। एक तो यह कि केरल की साक्षरता दर 90 प्रतिशत है। यहां के लोग सांवत हैं, तार्किक हैं। ये शिक्षित लोगों की



आदतें हैं। दूसरी बात यह कि केरल में 65 प्रतिशत हिंदू हैं और 45 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं। हर कैंककुलेशन में ये चीज आती है। ऐसे में केरल की तुलना किसी और राज्य से नहीं की जा सकती है। केरल भाजपा नेता राजगोपाल द्वारा पेश की गयी इसी ध्येयों को यह उलट दिया जाने तो समझा जा सकता है कि भाजपा जिन राज्यों में अपना जनाना बड़ा रही है उसकी दरअसल वजह यह है।

बहरहाल केरल की शिक्षित जनता ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाली गांधी — नेहरु परिवार की बेटी को वायनाड से रिकार्ड विजय श्री दिलकारक अपना मंत्रय सचिव केरल की कि देश की शिक्षित व लक्ष्मण जनता को गांधी — नेहरु परिवार की इस बेटी से काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। निश्चित तौर से प्रियंका गांधी ने न केवल अपने इतिहास को व पिता राहुल गांधी के साथ लंबे समय तक प्रगामनरी निगम में रहकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गुंथन वई बटिक पिता राजीव मा सोनिया व माई सुलोचि गांधी के चुनावों में अहम भूमिका निभाया। चुनावी राजनीति में भी पूरी महारत हासिल की है। राहुल गांधी ने वही नहीं कहा था कि यदि प्रियंका 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से नरेंद्र मोदी की विरुद्ध चुनाव लड़ती तो निश्चित रूप से ये मोदी को पराजित कर देती। क्योंकि 2019 में जितन वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने 4 लाख 79 हजार वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी वह अंतर इस बार घटकर 1 लाख 52 हजार रह गया है। वहीं मोदी के विरुद्ध कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले अजय राय ने 4 लाख 60 हजार वोट मिले थे। इस लिहाज से वायनाड से मोदी के विरुद्ध प्रियंका की उम्मीदवादी देश की राजनीति की विरुद्ध चुनाव लड़ती तो निश्चित रूप से मोदी को पराजित कर देती।

अपनी जीत के बाद पहली बार प्रियंका गांधी ने जितन वाराणसी में महादालता का आम्राव खाद्य किया वह भी काहिल — ए — राशिफ थे। उन्होंने कहा कि आपने मुझ पर जो मायास जताया है, उसके लिए मैं अपनी बहुत आभारी हूँ। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि समय के साथ, आपका वायनाड में यह महसूस हो कि यह जीत आपकी जीत है और जिस शख्स को आपने अपना प्रतिनिधि त्व करने के लिए चुना है वह आपकी

उम्मीदों और सपनों को समझता है और आपके लिए लड़ता है। मैं संसद में आपकी आज्ञाएं बनाने के लिए उत्सुक हूँ। निश्चित रूप से देश की जनता की भारतीय संसद में प्रियंका गांधी की आज्ञा उनका अदालत तथा उनके द्वारा देशहित में उठाये जाने वाले मुद्दों को सुनने के लिये बेहद उत्सुक है। तब लगाम दो देखके से प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार में अपनी जिस क्षमता व दक्षता का परिचय दिया है उससे कांग्रेस को भी लाभ हुआ है और कांग्रेस जगों में भी उत्साह का संचार हुआ है।

प्रियंका गांधी का संसदीय राजनीति में प्रवेश ऐसे समय में हुआ है जबकि संसदभर भाजपा साम दाम दंड भरे सभी तरफों अपनाकर संसद में बने रहना चाहती है तथा अपने अपेक्षित अतिवादी एजेंडे पर बलकर अपने सामने का बहसख्यवादी बना बनाया चाह रही हैं। जबकि कांग्रेस गांधी के सपनों के भारत के निर्माण की पक्षधर है। कांग्रेस सफ़िकेता व लोकतन्त्र की रक्षा की बात करती है। जबकि भाजपा के उद्देश्य नैतिकता व नैतिकता के बावत कर रहे हैं। उधर इण्डिया गठबंधन भी 2024 में अक्षा प्रदर्शन करने के बावजूद बीजेपी नेताओं के स्वार्थशर मन्त्रवृत्त विषय की भूमिका अदा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में ले देखकर कांग्रेस के लिये देश को उम्मीद मजबूत विश्वास देने की उम्मीद बनी हुई है। बलिक समय अहिंसा व धर्मनिरपेक्षता के निर्माण की आस भी केवल कांग्रेस पार्टी से ही है। राहुल गांधी निश्चित रूप से अपनी क्षमता से अधिक केरल कर सता से मुकाबला करने से लेकर पार्टी को मजबूत बनाने तक के लिये काफ़ी काम कर रहे हैं। परन्तु उक्त विरुद्ध सत्तावादी तरह तरह की सांसारिक रुढ़ि नरेंद्र गांधी के परिचय से ओझल करने तक की योजना बनाते बड़े हैं।

जिस तरह पूर्व में प्रियंका गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा के इक में आवाजे बुलंद की हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे उठाये हैं। दलितों/विशेष व गरीबों के लिये आवास उठाये हैं उन्हीं का जो प्रियंका गांधी के लोकसभा पहुँचने से काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। माना जा सकता है कि प्रियंका समाज के शोषित व पीड़ित समाज की आवाज तो बनीगी ही साथ ही राजनीति में अब नई इमारत भी लिखेंगी।

—अभिनय आकाश—

वैसे तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी दो साल का वक्त शेष है। लेकिन विभिन्न मस्जिदों और स्थलों पर अतिक्रमण के दावे आए दिन देखने को मिल रहे हैं। मामला स्थानीय अदालतों से शुरू होते हुए विभिन्न कोर्ट तक पहुँच भी पाया है। जिसने सूबे के सिपायों की हार को भी गम कर दिया है। तीन याचिकाएँ हाल के हफ्तों में उत्तर प्रदेश में दायर की गई हैं, जबकि अजमेर शरीफ दरगाह में सदैवध की मांग करते हुए एक याचिका राजस्थान में अजमेर अदालत में दायर की गई है। वहीं दिल्ली के जामा मस्जिद को लेकर हाई कोर्ट में अहम सुनवाई है। जामा मस्जिद के आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाने और अतिक्रमण को हटाने की मांग वाला याचिकाओं से जुड़ा एक मामला पर सुनवाई होगी।

19 नवंबर को यूपी के चंदौरी से एक याचिका दायर कर संभल की शाही जामा मस्जिद पर हिंदू अधिकार का दावा किया गया। अदालत ने उसी दिन मस्जिद के संरक्षण का आदेश दिया, और प्रशासन ने शाम तक यह सर्वेक्षण भी कर लिया। संभल में जह से जामा मस्जिद में गरी मस्जिद होने का दावा किया गया है, उसके बाद से संभल सीटी नगरी के कई सड़क सामने आए हैं। संभल में प्राचीन मस्जिद की परिक्रमा पर बने सड़क सामने आए थे। ऐसे कई मस्जिद आर भी संभल में मौजूद हैं। वहीं संभल प्रशासन ने इन मस्जिदों का जीर्णोद्धार शुरू कर दिया है। संभल के मस्जिदों का स्वरूप बिचकल वैसा ही करने की याचिका है जैसा आकांताओं के अत्याचार से पहले हुआ करता था।

24 नवंबर को मस्जिद के दूसरे संरक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी जिसमें कम से कम चार लोग मारे गए थे। तब से बढ़ाव में शमशी शाही मस्जिद के साथ-साथ जौनपुर में अदालत मस्जिद पर समान दावे करने वाली अदालतों में दायर याचिकाओं में डेवलपमेंट भी देखने को मिला है। विश्वास ने निचली अदालतों द्वारा इन याचिकाओं को स्वीकार करने के तरीके और राज्य प्रशासन द्वारा अपने अधिकारों को लागू करने में दिखाई गई तत्परता से परहेज हुआ करता था।

सुप्रीम कोर्ट ने अब पूजा स्थल (विशेष प्राधान्य) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है, जो यह निर्धारित करती है कि पूजा स्थलों को ओपेनकर सभी पूजा स्थलों की प्रकृति अयोध्या में जो उस समय मुकदमेबाजी के अंत में था, उसे वैसे ही बनाए रखा



जाएगा जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था। वाराणसी में ज्ञानपीठ मस्जिद और मधुवा में इंदगाह मस्जिद पर हिंदू अधिकारों का दावा करने वाली याचिकाएँ 2021 में दायर की गईं। नई याचिकाओं के मद्देनजर एनडीए के आदेशों की हिंदू राजनीति के ब्रांड को बढ़ावा मिल सकता है, जिसे कई लोग भाजपा की मानक लाइन से अधिक आक्रामक मानते हैं। मोरखपुर में मोरखण्ण नगर, जिसके प्रमुख अतिरिक्तनाथ हैं, अयोध्या एंफोर्सेस से निरक्षरता से जुड़ा हुआ था, जिसकी परिणति यौगि अदालत के 2019 के फैसले के मद्देनजर जनवरी 2024 में राम मंदिर के निर्माण में हुई थी। 2025 की शुरुआत में सुपी का प्रयागराज में महाकुंभ की मेजबानी कराग, जिसे सबसे बड़ा हिंदू सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है। इस कार्यक्रम को सम्बन्धी बनाने के लिए सीएसए पहले ही आरएसएस के अधिक अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, जहाँ हिंदू, संभल की सभी जातियों और संसदाय का प्रतिनिधित्व किया जा सके। इसे हिंदुत्व नेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय छवि को बढ़ावा देने के लिए आदिवासीयों की कोशिश के रूप में भी देखा गया है।

कानून-व्यवस्था, शासन और कल्याण के कोटिस्थान में हिंदुत्व का तत्काल महाराज जी (अदिवासीय) राजनीति को सही स्तर पर देखा है। विश्वास ने हिंदुत्व को और आगे बढ़ाना शुरू किया। इस बात से इनकार करते हुए कि सरकार का याचिकाओं से कोई लेना-देना है, उन्होंने यह भी दावा किया है (याचिकाकर्ता) सभी व्यक्ति हैं जो न तो भाजपा से जुड़े हैं और न ही सीएस परियार हैं। जैसे मामले अदालतों में हैं। लेकिन अगर कोर्ट के आदेश के बावजूद दूसरा पक्ष परेशानी पैदा करता है तो यूपी सरकार के तत्काल हवाई फौज तय है।

याचिकाओं पर विपक्षी पार्टियों की ओर से भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। यूपी में प्रमुख विपक्ष सभा ने संभल में हुई मीलों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और भाजपा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। हालाँकि, सभा प्रमुख अतिरिक्तनाथ यादव ने अभी तक संभल के कोर्ट प्रयास नहीं किया है। विधानसभा में केवल सभा के नेता प्रतियक्ष (एलओपी) माता प्रसाद पांडे ने 30 नवंबर को पार्टी नेताओं की प्रतिनिधित्वित्व से सफा शहर का दौरा करने का प्रयास किया, जिसे प्रशासन ने विफल कर दिया। कई लोग इसे भाजपा को मामले का धरोहरक करने से रोकने के लिए इस मुद्दे पर सावधानी से आगे बढ़ने के एनपी के कदम के रूप में देखते हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने केवल इस मुद्दे पर मुखर नहीं है, बल्कि पूजा स्थल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभल जाने की भी कोशिश की, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस काफ़ी समिति ने बैठक में पारित अपने एक प्रयास में पूजा स्थल और नियम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संभल याचिका के बाद यूपी कांग्रेस की अल्पसंख्यक शाखा ने इस अधिनियम के कठिना उल्लंघन के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। कांग्रेस का अभियान 6 दिवसीय को बाबाई मस्जिद विध्वंस की बरसरी पर शुरू किया गया था, जो संविधान के निर्माता भी अंग अंगेडकर की पुण्य तिथि है। यूपी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यहां तक घुआरोप के लाने में कितनी कुशल है। यूपी पीठों के एक नेता ने कहा कि ऐसे समय में जब विश्वास समाज को जाति के आधार पर बाँटने पर आमदा है, हमें हिंदुत्व को और आगे बढ़ाना होगा। इस बात से इनकार करते हुए कि सरकार का याचिकाओं से कोई लेना-देना है, उन्होंने यह भी दावा किया है (याचिकाकर्ता) सभी व्यक्ति हैं जो न तो भाजपा से जुड़े हैं और न ही सीएस परियार हैं। जैसे मामले अदालतों में हैं। लेकिन अगर कोर्ट के आदेश के बावजूद दूसरा पक्ष परेशानी पैदा करता है तो यूपी सरकार के तत्काल हवाई फौज तय है।

बातचीत करने के लिए बेहतर स्थिति में लाया।

